



न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज०)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :- 33/2018

पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक २७/१२/१७

श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

पुरजान पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा  
राज०

(प्रार्थी)

बनाम्

1. सन्तरा पत्नी शिवराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट  
जिला दौसा राज०
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तह० लालसोट जिला दौसा  
राज०

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : १५/१२/१७

प्रस्थित :- श्री कमलेश कुमार सैनी एडवोकेट - प्रार्थी की ओर से  
अप्रार्थी संख्या १ की ओर से श्री वैभव गुरावा एडवोकेट

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत  
किया गया कि प्रार्थी ग्राम डिगो तहसील लालसोट का काश्त पेशा व्यक्ति है।  
जिसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं० ८८७/३२६  
रकबा १० बीघा वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त आराजी  
भूमि पर वर्तमान में भी प्रार्थी की फसल काश्त है तथा उक्त आराजी भूमि में  
अप्रार्थी संख्या १ का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार निहित नहीं

उपखण्ड अधिकारी  
लालसोट जिला दौसा (राज०)

है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं० 886/326 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त आराजी भूमियो को प्रार्थना पत्र में आराजी वादग्रस्त भूमिया सम्बोधित किया जा रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-73 किता 2 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश की जा रही है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि खसरा नं० 887/326 की नक्शासीट में तरमीम नहीं हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि खसरा नं० 886/326 के स्थान पर गलत प्रकार से तरमीम करवा ली जिसकी जानकारी प्रार्थी पक्ष को नहीं रही जबकि खसरा नं० 887/326 की नक्शासीट में की गई तरमीम की जगह पर प्रार्थी का पूर्व से ही कब्जा काशत चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी की उक्त स्थल पर फसल काशत हो रही है। प्रार्थी अपनी तन्हा खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक वर्षों से काबिज रहकर काशत कर लाभान्वित होता चला आ रहा है तथा प्रार्थी पूर्व समय से आज तक उसी जगह काबिज है तथा उक्त जगह से अप्रार्थी संख्या 1 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि की आड में खसरा नं० 326 में जगह जगह अतिक्रमण भी कर रखा है तथा उसने राजस्व कर्मियों से मिली भगत करके अपनी भूमि की तरमीम प्रार्थी की काबिज जगह पर करवा ली गई। जिसमें राजस्व कर्मियों द्वारा बिना मौका देखे ही बिना किसी प्रक्रिया के ही प्रार्थी की काबिज जगह पर अप्रार्थी संख्या 1 का कदापि कब्ज नहीं रहा है न ही वर्तमान में है अतएव अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मियों से मिली भगत करके करवाई गई नक्शासीट में तरमीम बमुकाबिले प्रार्थी आरंभतः अवैध तथा प्रभाव शून्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नक्शासीट में करवायी गई तरमीम की जानकारी प्रार्थी को नहीं रही परन्तु दिनांक 15-10-2017 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को चेतावनी देते हुए कहा कि अब की मर्तबा हम इस जगह पर तुम्हें फसल काशत नहीं करने देंगे यह जगह हमारी है। तब प्रार्थी ने कहा कि यह भूमि मेरी है वर्षों से यही काशत करता हूँ इसी में मेरा मकान बोरिंग सब कुछ है तब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को बेजा चेतावनी दी गई कि इस जगह की तरमीम मैंने हमारी जमीन की करवा ली है तथा यहां से हट जाओ वरना जबरन बेदखल कर कब्जा करेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 की

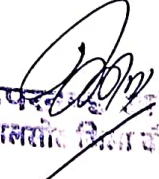
इसी बेजा चेतावनी से वाद कारण पैदा होकर प्रार्थी को अपने हक व हकूको की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र सेवामे पेश करना लाजिमी आया। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि को अपनी एवं अपने परिजनो की अथाह मेहतन व लागत लगाकर समतल, उपजाउ व कृषि योग्य बनाया है जिसमे प्रार्थी के निवास स्थान कृषि संसाधन वृक्ष आदि स्थापित है तथा वर्षो से प्रार्थी इसी जगह पर काश्त करके अपना तथा अपने परिजनो का गुजर बसर करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त जगह से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही रहा है न ही वर्तमान मे है। प्रार्थी माननीय न्यायालय हाजा से सरंक्षण प्राप्त करके वादग्रस्त आराजी भूमि बाबत इस आशय की उद्घोषणा करवाने को अधिकृत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि खसरा नं0 889/326 रकबा 10 बीघा की नक्शासीट मे करवाई गई तरमीम बमुकाबिले प्रार्थी आरंभतः अवैध तथा प्रभावशून्य है उक्त तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लालसोट को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थिति मे वास्तविक रकबेनुसार वास्तविक जगह पर पुनः प्रार्थी की भूमि की तरमीम किये जाने हेतू आदेशित फरमाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि की नक्शासीट मे की गई तरमीम की आड लेकर उक्त भूमि का रहन, बय, हस्तान्तरण नही करे तथा प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम की आड लेकर जबरन बेदखल कर फसल नही करे तथा प्रार्थी की फसल प्राकृतिक पैदावार बोरिंग डोल कृषि संसाधनो को किसी भी प्रकार की क्षति व नुकसान कारित नही करे न करावे स्वयं अपने सेवको साथियो परिवारजनो रिश्तेदारो सहित पाबन्द रहे तथा अप्रार्थी संख्या 2 उक्त आराजी भूमि में वर्तमान राजस्व अभिलेख मे बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व अनुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम रखें एतदर्थ उक्त प्रार्थना पत्र सेवामें प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज करके अप्रार्थीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के ओर से श्री वैभवराज गुरावा एडवोकेट उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी

उपर  
लालसोट

ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के चरणों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तरमीम गलत प्रकार से नहीं बल्कि कब्जेनुसार हल्का पटवारी व गिरदावर की मौजूदगी में राजस्व एजेन्सी के कर्मचारीयों द्वारा विधिनुसार सही ढंग से की गई है जो विगत 20-25 वर्षों पूर्व ही चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 की तरमीम शुदा खातेदारी आराजी खसरा नं० 886/326 से प्रार्थी का किसी भी प्रकार से संबंध सरोकार वास्ता नहीं है बल्कि केवल मात्र मिन अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान परेशान करने की गर्ज से उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अपने कलूषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माननीय न्यायालय को गुमराह करने की चेष्टा कर रहा है क्योंकि प्रार्थी को विगत 20-25 वर्षों से मिन अप्रार्थी संख्या 1 की तरमीम की जानकारी रही है जो कि सर्वथा ही कानून के प्रावधानानुसार की गई है एवं उसी जगह मिन अप्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने के लिए प्रार्थी द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी को केस प्रथम दृष्टया साबित होता हो तथा यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवाया जा सकता है। और नाही गलत तथ्यों की आड लेकर माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नं० 887/326 रकबा 10 बीघा एवं मिन अप्रार्थी की आराजी खसरा नं० 886/326 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट दोनों पृथक पृथक आराजीयात है तथा मिन अप्रार्थी की आराजी में प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार वास्ता नहीं है क्योंकि मिन अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त आराजी की तरमीम विधिनुसार विगत 20-25 वर्षों पूर्व से हो रही है जिसकी सीमा की जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से ही रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

  
उपर्युक्त अधिकारी  
तालुका न्यायाधीश (राज.)

प्रकरण मे प्रार्थना पत्र को तय कराने हेतु तीन बिन्दुओ प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षती को देखना है।

मेरी राय मे उक्त तीनो बिन्दुओ पर एक साथ निर्णय किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि पर लगभग 20-25 वर्षो पूर्व से आधिपत्य होने का कथन किया है एवं यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी अथाह मेहनत एवं लाखो रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया है एवं विवादित भूमि पर आधिपत्य आज तक बदस्तुर चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी पूर्व मे तरमीम शुदा पृथक पृथक भूमि रही है जिसमे प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है। मेरी राय मे प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अपना कब्जा विवादित भूमि पर होने का कथन जरूर अंकित किया है चुकी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए तीन बिन्दुओ का साबित किया जाना जरूरी है।

1. प्रथम दृष्ट्या केस
2. सुविधा की तुला
3. अपुरणिय क्षति

जहां तक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का यदि अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तोवजात प्रस्तुत किये है उनसे भी भली प्रकार यह साबित नही हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि सिवाय चक भूमि है। ऐसी सुरत मे प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या साबित नही माना जाता है।

जहां तक सुविधा की तुला का प्रश्न है अप्रार्थी संख्या 1 भूमि का रिकार्डेड खातेदार है यदि अप्रार्थी को मेरे विनम्र मत में अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है तो असुविधा प्रार्थी को नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 को ही होगी इस प्रकार अपूरणीय क्षति का प्रश्न है कि ऐसी क्षति जिसकी भरपाई मूल्य से नही की जाती सकती हो हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से प्रथम दृष्ट्या केस दस्तावेजी साक्ष्य से व मौखिक साक्ष्य से तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपुरणिय क्षति का जहां तक प्रश्न है वह भी अप्रार्थी संख्या 1 को ही होने का अंदेशा है। ऐसी स्थित मे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तिनी बिन्दु

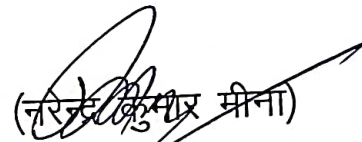
प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपुराणिय क्षति इन तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से आराजी खसरा नं. 887/326 रकबा 10 बीघा भूमि वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर

खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( (नरेंद्र कुमार मीना)

उपस्थान्त अधिकारी लालसोट  
लालसोट जिला दौसा (राज०)